दिल्ली में एनडीएमसी की अनोखी पहल: 'सुविधा कैंप' में 120 से ज्यादा शिकायतों का तुरंत समाधान!

नई दिल्ली। दिल्ली में नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने नागरिकों को केंद्र में रखकर पारदर्शी और सहभागी शासन की ओर एक और अहम पहल तैयार की है. जय सिंह रोड स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मासिक सुविधा कैंप में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ, बल्कि सेवाओं की पहुंच भी सहज हुई. इस कैंप में एनडीएमसी के विभिन्न विभागों, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, बागवानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कर, संपदा और प्रवर्तन आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इसमें कुल 120 से अधिक शिकायतें मौके पर प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान वहीं कर दिया गया, यह नागरिक सेवाओं के प्रति परिषद की तत्परता और जिम्मेदारी का स्पष्ट उदाहरण है.

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

● वर्ष: 23 ● अंक: 172 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 08 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

ब्रिक्स में पीएम मोदी के रुख का कांग्रेस ने किया समर्थन, कहा- भारत आतंकवाद से दृढ़ता से लड़ेगा

नई दिल्ली । ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के रुख का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत ने बता दिया है हम आतंकवाद से पूरी दृढ़ता से लड़ेंगे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा था कि आतंकवाद की निंदा सिद्धांत का मामला होना चाहिए, सुविधा का नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ आवाज और मुखर होनी चाहिए थी। मंच पर सदस्य देशों की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक चिंताओं को भी उठाया जाना चाहिए था। भारत ने लगातार वैश्विक शांति और न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश आतंकवाद से अडिग संकल्प के साथ लड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पहलगाम में हमला हो में हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोग पकड़े जाएं - इससे पता चल जाता कि उन्हें किसने प्रशिक्षित किया और उनका समर्थन किया। ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण है और इससे विश्व स्तर पर अधिक सम्मान मिलता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ब्रिक्स देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी पर ट्रंप पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि ब्रिक्स उन देशों की रक्षा के लिए है जो इसमें शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी भारत दौरे पर

ऐसी ही चेतावनी दी थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी को हंसना या हल्के में जवाब नहीं देना चाहिए था। उन्हें दृढ़ रहना चाहिए था और ट्रंप को याद दिलाना चाहिए था कि ब्रिक्स अपने सिद्धांतों पर काम करता है और अपने संस्थापक उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मतदाता सूची संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज अव्यावहारिक हैं। अगर प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भाजपा के खिलाफ पारंपरिक मतदाता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाता का मतदाता सूची में बने रहना मुश्किल हो जाए, तो यह चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल उठाता है। अगर चुनाव आयोग उन्हें हटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदाताओं के अधिकार को बरकरार रखा है। हम इस सिद्धांत पर कायम रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए एक डूबता हुआ जहाज है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जैसे सम्मानित नेता के बेटे होने के बावजूद अशांत राजनीतिक जल में तैरते रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंदरूनी दरारें चौड़ी हो गई हैं और गठबंधन के कई सदस्य चुनाव से पहले ही बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। एनडीए के नेताओं को पता है कि वे कई सीटें हारने जा रहे हैं। उनकी हताशा नजर आ रही है। जबकि वे केंद्र सरकार बना रहे हैं, वे राज्य पर अपनी पकड़ खो रहे हैं। इससे उनके अपने सहयोगियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

दिल्ली में एक बार फिर मांस-मछली बैन की मांग, बीजेपी विधायक ने सीएम-एलजी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से मांस-मछली पर रोक लगाए जाने की मांग उठने लगी है. नवरात्रि से पहले बीजेपी विधायक ने इच्छा जताई है कि कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर मीट की दुकानें बंद की जाएं. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि नवरात्रि की तरह ही कांवड़ यात्रा के दौरान भी यह नियम फॉलो किया जाए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी विधायक विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने बताया, "जैसा कि आपने नवरात्रि के दौरान देखा, हमने नौ दिनों तक 70-80% दुकानें बंद रखने में बड़ी सफलता हासिल की. मुख्यमंत्री ने विचार करने के लिए समय मांगा है और एलजी भी इस पर विचार कर रहे हैं. मैं गृह मंत्री से भी मिलूंगा. इससे पहले हिंदू सेना ने भी सीएम और राज्यपाल को इसी मांग के तहत पत्र लिखा था. हिंदू सेना ने भी अनुरोध किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर आने वाले सभी बूचड़खानों और दुकानों को यात्रा अवधि तक बंद किया जाए. वहीं, विष्णु गुप्ता ने यह मांग भी रखी है कि यात्रा मार्ग पर आने वाले सभी रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच हो, ताकि कोई पहचान छुपाकर सामान न बेच सके. हिंदू सेना ने दावा किया है कि पिछले साल कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ियों को खाना परोसा था. इससे श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया था.

दिल्ली के शकूरबस्ती को जय श्रीरामपुरम करने की मांग, समर्थन जुटाने में लगे बीजेपी विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदलने की मांग एक बार फिर चर्चा में है. शकूरबस्ती विधानसभा से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर जय श्रीरामपुरम करने की मांग उठाई है. इसके लिए वे इलाके की आरडब्ल्यूए से समर्थन जुटा रहे हैं और कई आरडब्ल्यूए सदस्य इस नाम के समर्थन में लिखित पत्र भी दे रहे हैं. विधायक का कहना है कि यह नाम क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है. इससे पहले भी दिल्ली में नाम बदलने की मांग उठती रही है. भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम शिव विहार करने का प्रस्ताव लाने की बात कही थी, हालांकि पिछली बार उन्होंने यह प्रस्ताव सत्र के दौरान वापस ले लिया था. लेकिन उनका कहना है कि मानसून सत्र में इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे. वहीं, भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ और अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम करने की मांग की है. दिल्ली में बार-बार उठ रही इन नाम बदलने की मांगों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बता रहे हैं. हालांकि किसी भी क्षेत्र का नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया और कई स्तरों पर मंजूरी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह मांग प्रस्तावों से आगे बढ़ती है या नहीं.

हर मंडल, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे; संघ ने घर-घर संपर्क की भी योजना बनाई

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में देश की सुरक्षा के साथ-साथ मणिपुर के हालात पर भी चर्चा की गई है। मणिपुर में हालात काफी बेहतर हुए हैं, हालांकि इसे पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। संघ का मानना है कि देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हासिल कर रहा है। हालांकि, इस विकास को हर दृष्टि से सर्व समावेशी बनाने के लिए संघ काम करेगा। इसके लिए हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 11360 से अधिक सामाजिक सद्भाव बैठकों को आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस बार विजयादशमी को संघ के ड्रेस कोड में स्वयंसेवक पहुंचेंगे और लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समाज को सुदृढ़ करने के लिए घर-घर संपर्क करने की संघ की योजना है। संघ के सभी संगठनात्मक 924 जिलों में राष्ट्र और हिंदुत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा कराई जाएगी। संघ ने हर समाज और हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई है। इनके माध्यम से हिन्दू समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने की योजना है। संघ ने अपनी इस बैठक में माना है कि देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें देश-विदेश, शिक्षा, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ संघ पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य समाज को हर क्षेत्र में भागीदार बनाने और समाज को सर्व समावेशी बनाना है।

पंच परिवर्तन के द्वारा देश-समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच आयोजित प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न हुए हैं। 40 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में 17609 लोगों ने प्रशिक्षण हासिल किया। 8812 स्थानों से आये शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 40 से 60 वर्ष की आयु के 4270 लोगों ने संघ शिक्षा वर्ग में हिस्सा लिया है। इसमें पढ़े-लिखे वर्ग और किसान-श्रमिक तक सभी शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रान्त प्रचारक बैठक 4-6 जुलाई को दिल्ली के झंडेवालान स्थित संगठन के कार्यालय केशवकुंज में हुई।

8 महीने में बदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर! प्रगति मैदान-भैरो मार्ग टनल को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रगति मैदान-भैरो मार्ग पर टनल निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है. ये प्रोजेक्ट अगले आठ से नौ महीनों में पूरा कर ली जाएगी. यह जानकारी आज (7 जुलाई) ही दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी. उन्होंने कहा कि जैसे ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी, टनल का शेष निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा. मंत्री वर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ मिलकर इस निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की. पीटीआई के अनुसार, यह टनल प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय दिल्ली से सराय काले खां, आईएसबीटी, आश्रम और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक और सुगम मार्ग प्रदान करना है. समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि दो साल पहले यमुना में आई बाढ़ और पिछली सरकार की अनदेखी व लापरवाही के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस सरकार में वो चीजें नहीं दोहराई जाएंगी और कार्य जल्द से जल्द पूरा होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि अब जैसे ही केंद्र सरकार की मंजूरी मिलेगी, विभाग पूरी गति से काम करेगा और तय समयसीमा के भीतर इस बहुप्रतीक्षित टनल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल इस अंडरपास का केवल आधा हिस्सा ही यातायात के लिए खोला गया है, क्योंकि दूसरी ओर की रैंप अब तक पूरी नहीं हो सकी है. यह रैंप मुख्य प्रगति मैदान टनल के साथ ही चालू किया जाना था, लेकिन कार्य अधूरा रह गया. इससे आम नागरिकों को अभी पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है और ट्रैफिक दबाव बना हुआ है.

दंगा साजिश मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू, अब 11 जुलाई से होंगी दलील

नई दिल्ली। 2020 दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सोमवार से कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने आरोपी शिफा-उर-रहमान की पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद ने 35 पन्नों का एक नोट दायर किया, जिसमें उनकी दलीलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिफा-उर-रहमान के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और यह मामला संदेह के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि साजिश साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं है। कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई में हुई असुविधाओं का हवाला देते हुए सुनवाई को कल (8 जुलाई) के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया, क्योंकि वकीलों की हड़ताल के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित होना मुश्किल हो रहा है। खुर्शीद ने हड़ताल समाप्त होने के बाद कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने में कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने 11 जुलाई की तारीख का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई 11:30 बजे निर्धारित की गई।

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे ओवैसी, कहा- प्रक्रिया के लिए और समय दिया जाए

नई दिल्ली ।बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर एआईएमआईएम का प्रतिनिधिमंडल सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। एआईएमआईएम के प्रमुख अगर 15-20 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट भी गए, तो वे अपनी नागरिकता भी खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाएगा, तो वह व्यक्ति न केवल अपना वोट खो देगा, बल्कि यह उसकी आजीविका का भी मुद्दा है। हमारा एकमात्र मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इस तरह की कवायद को कैसे लागू कर सकता है? लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और हमने व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए इन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने रखा है। बिहार में एमआईएमआईएम के राज्य प्रमुख और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि पुनरीक्षण की तिथि बढ़ा दी जाए या रोक लगा दी जाए क्योंकि राज्य में कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं, कई प्रवासी मजदूर हैं और मानसून का मौसम भी है। राज्य में केवल 2 फीसद आबादी के पास पासपोर्ट है और स्नातकों की संख्या 14 फीसदी है।

शांति बस एक भ्रम, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें; राजनाथ सिंह की रक्षा अधिकारियों को नसीहत

नई दिल्ली ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि शांति का समय सिर्फ दिखावटी होता है, असल में कभी भी हालात बदल सकते हैं। इसलिए देश को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में जो साहस दिखाया, उसने पूरी दुनिया में भारत के रक्षा क्षेत्र की साख बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में अब ज्यादातर रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। पहले हम कई जरूरी हथियार और उपकरण विदेश से मंगवाते थे, लेकिन अब देश में ही आधुनिक हथियार बनने लगे हैं। इससे न सिर्फ हमारी सेना मजबूत हो रही है, बल्कि दुनियाभर में भारत के रक्षा उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो साहस और रणनीति दिखाई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। देश में बने हथियारों और मंचों की मजबूती देखकर कई देशों ने भारत के रक्षा उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाई है। यह हमारी आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे माहौल कितना भी शांत क्यों न लगे, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी अप्रत्याशित घटना कभी भी हो सकती है। इसलिए सेना से लेकर रक्षा मंत्रालय तक, सभी को अपने आर्थिक और सैन्य ढांचे को ऐसा बनाना होगा कि कभी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि रक्षा खर्च को सिर्फ खर्च न समझा जाए, बल्कि इसे देश के विकास का एक बड़ा निवेश माना जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में सैन्य खर्च 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसे में भारत में रक्षा उद्योग के लिए बड़े मौके हैं। यह क्षेत्र अब देश की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है। रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे खुद को सिर्फ नियंत्रक न समझें, बल्कि सहायक की भूमिका निभाएं। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ उन्हें और अधिक लचीला और तेज बनना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहरी जांच पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद की आंतरिक समीक्षा करें, तभी रक्षा मंत्रालय और देश की सुरक्षा प्रणाली और मजबूत हो सकेगी।

नई दिल्ली क्षेत्र में लगेंगे छह लाख पौधे, हर सड़क होगी गुलजार; एनडीएमसी ने योजना की तैयार

नई दिल्ली। राजधानी का दिल कहे जाने वाले नई दिल्ली क्षेत्र की मानसून के दौरान सूरत बदलने की तैयारी है। एनडीएमसी ने क्षेत्र को हरा-भरा करने के लिए करीब छह लाख पौधे और झाड़ियां लगाने की कवायद शुरू की है। इसके अलावा जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली को हरा-भरा बनाने की शुरू की गई योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस पहल को वायु गुणवत्ता सुधार, पर्यावरणीय संतुलन और जनजीवन को राहत देने की दिशा में एनडीएमसी ने बड़ा कदम बताया है। एनडीएमसी के अनुसार, मानसून की नमी और मिट्टी की उपयुक्तता को देखते हुए जुलाई-अगस्त में पौधरोपण होगा। यह योजना सड़क किनारे, पार्कों, खाली सार्वजनिक स्थानों और खास ग्रीन बेल्ट को केंद्र में रखकर बनाई गई है। इसके तहत सजावटी झाड़ियों के साथ-साथ पर्यावरण व स्थानीय जलवायु के अनुकूल छायादार और ऑक्सीजन उत्सर्जक पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजपथ, जनपथ, तुगलक रोड, अशोक रोड, शंकर रोड और अकबर रोड को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। पौधों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार टीमें भी बनाई गई हैं जो सिंचाई आदि की नियमित निगरानी करेंगी। एनडीएमसी इस वर्ष चार प्रमुख एवेन्यू में हरियाली सुधार और ग्रीन लैंडस्केपिंग कार्य शुरू करेगी। यहां उन्नत किस्म के सजावटी पौधे, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और ऊर्जा-कुशल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रीन जोन टिकाऊ और सुंदर दिखे। यह पहल जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी। एनडीएमसी अब तक 40 एवेन्यू विकसित कर चुकी है। एनडीएमसी ने गत वर्ष 11,000 से अधिक पौधे और करीब 14 लाख झाड़ियां लगाई थीं जिससे राजधानी का लैंडस्केप बदला। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार मानसून के दौरान सड़क किनारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण का नया लक्ष्य रखा है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल का कहना है कि हरियाली अभियान न केवल नई दिल्ली के पर्यावरण को सशक्त बनाएगा, बल्कि यह लोगों को प्रकृति से जोड़ने, शहरी जीवन में राहत देने और राजधानी को मॉडल ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मेरा सामान पैक है, बंगला खाली करने में देरी पर बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली । सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बताया है कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें देरी हुई है. उनका कहना है कि उनकी बेटियां रेयर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिनके लिए उन्होंने घर में ही आईसीयू का सेटअप किया है और उनके किसी नए घर में शिफ्ट होने के लिए उनकी जरूरतों का ख्याल रखना होगा. जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई रेजीडेंस छोड़ने के बाद तीन मूर्ति मार्ग पर आवंटित सरकारी आवास में रहेंगे. पूर्व सीजेआई ने बताया कि उन्होंने सामान पैक कर लिया है और दो हफ्ते में वह आवास खाली कर देंगे. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ अभी दिल्ली में 5 कृष्णा मेनन मार्ग पर टाइप 8 बंगले में रह रहे हैं. बार एंड बेंच से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने अपना सामान और फर्नीचर पैक कर लिया है. सिर्फ रोजाना इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर बाहर है, जिसे वह ऐसे ही ट्रक में रखकर नए घर ले जाएंगे. इस सबमें मुश्किल से 10 दिन और लगेंगे या ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते लग सकते हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि पहले भी कई जजों का बंगले में रहने के लिए समय बढ़ाया गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर, 2024 में सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे. उन्हें इस आवास में रहते हुए आठ महीने हो गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आवास खाली करवाने के लिए कहा है. चिट्ठी में बताया गया कि उन्हें अस्थाई निवास के तौर पर टाइप 7 बंगला मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से अनुरोध करके

उन्होंने पुराने बंगले में 30 अप्रैल, 2025 तक रहने के लिए अनुमति मांगी थी. पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि उन्हें तीन मूर्ति मार्ग पर जो नया बंगला मिला है, उसमें काम चल रहा था और ठेकेदार ने जून तक काम खत्म करने की बात कही थी. उन्होंने बताया कि दो साल से वह बंगला खाली था क्योंकि कोई भी जज इस बंगले में रहने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए उसमें काफी काम होना था. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने तीन महीने के लिए किराए पर भी घर लेने का सोचा, लेकिन कोई भी ऑनर इतने कम समय के लिए घर देने को तैयार नहीं है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उनकी बेटियां अब 16 और 14 साल की हैं, वह अब 6 साल की छोटी बच्ची नहीं हैं. उनकी अपनी गरिमा, निजता और जरूरतें हैं. छोटी-छोटी चीजें हैं जैसे... बाथरूम के दरवाजे का साइज ताकि उनकी व्हीलचेयर अंदर जा सके. जस्टिस चंद्रचूड़ की दो बेटियां प्रियंका और माही, जिन्हें उन्होंने गोद लिया है. दोनों नेमालाइन मायोपैथी नाम के डिसऑर्डर की शिकार हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने किराए पर लेने के लिए कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन उनमें से कोई एक फाइनल करने के लिए दो महीने और चाहिए थे इसलिए उन्होंने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना से 28 अप्रैल तक उस बंगले में रहने के लिए अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह कृष्णा मेनन मार्ग बंगले में शिफ्ट नहीं होंगे इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ वहां रह सकते हैं. जब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई सीजेआई बने तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर वह उन्हें थोड़े समय रहने देंगे तो अच्छा होगा और अगर नहीं तो वह नियम के अनुसार मार्केट वैल्यू पर बंगले का किराया देने के लिए तैयार हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका बंगला खाली करने में देरी का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने बताया कि उनके घर में छोटा सा आईसीयू सेटअप है. जब वह शिमला में थे तो उनकी एक बेटी की तबियत अचानक बिगड़ गई, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें फ्लाइट से उसको चंडीगढ़ लाना पड़ा. 44 दिन उनकी बेटी आईसीयू में रही. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अभी भी ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब पर है, जिसको साफ करना पड़ता है, कभी कभी आधी रात को बदलना भी पड़ता है.

क्षमा मांगना या देना भावनात्मक और मानसिक कल्याण का एक पहलू

वैश्विक स्तरपर भारतीय सभ्यता,संस्कृति, मूल्यों मर्यादा और आध्यात्मिकता की सजगता दुनिया में कहीं नहीं है हमारी सभ्यता के अनेक मोतियों में से एक माफी मांगना या देना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है जो माफ करता है पुरानी बातों को भूल जाता है वही सबसे बड़ा दानी है क्योंकि क्षमादान जैसा कोई दान नहीं यहभारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति है ! मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, हमसे अगर गलती हो जाए तो हमें शांत स्वभाव से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें कि माफी मांगने से हमेशा रिश्ते मजबूत ही होंगे, दो लोगों के बीच कभी बैर नहीं होगा। माफ करने या माफी मांगने की आदत से यह मालूम पड़ता है कि व्यक्ति तुच्छ भावों के मुकाबले में रिश्ते को ज्यादा अहमियत देता है।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 जुलाई 2025 को वैश्विक माफी दिवस है,चूंकि क्षमा दिवस मनाने से खुद को व दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे एक अधिक दयालू और सहानुभूतिपूर्ण दुनियाँ को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,क्षमा मांगना या देना भावनात्मक और मानसिक कल्याण का एक पहलू है जो सद्भाव और शांति स्थापित करने में मदद करता है। साथियों बात अगर हम वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई 2025 के महत्व और शक्तियों को समझने की करें तो,यह दिवस हमारे जीवन में क्षमा की शक्ति और महत्व को समर्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह द्वेष को दूर करने, पिछले घावों को भरने और समझ और सुलह की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर चिंतन करने का दिन है। क्षमा भावनात्मक और मानसिक कल्याण का एक पहलू है, जो व्यक्तियों और समुदायों को सद्भाव और शांति से आगे बढ़ने में मदद करता है। वैश्विक क्षमा दिवस लोगों को खुद को और दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे एक अधिक दयालु और सहानुभूति पूर्ण दुनिया को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक स्तरपर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों मर्यादा और आध्यात्मिकता की सजगता दुनिया में कहीं नहीं है हमारी सभ्यता के अनेक मोतियों में से एक माफी मांगना या देना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है जो माफ करता है पुरानी बातों को भूल जाता है वही सबसे बड़ा दानी है क्योंकि क्षमादान जैसा कोई दान नहीं यहभारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति है! साथियों बात अगर हम मानव जीव में क्षमा भाव की करें तो, क्षमा भाव जिसके भीतर विकसित हो जाता है,वह व्यक्ति समाज में आदरणीय माना जाता है। किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना औरआत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा परोपकार है। कितना आसान है किसी से अपनी गलती की माफी मांगना और उससे भी ज्यादा आनंद तब मिलता है, जब वह व्यक्ति हमें माफ कर देता है। क्षमा का शस्त्र जिसके पास है, उसका दुष्ट मानव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह बिना तिनकों की पृथ्वी पर गिर कर अग्नि खुद ही शांत हो जाती है। साथियों बात अगर हम क्षमा मांगने की परिस्थिति की करें तो, यदि हमसे वाकई गलती हो गई है तो गंभीरता से क्षमा मांगें। कोई स्पष्टीकरण दें, हमारी गलती से वह विचलित है और हमारे कारणों को समझने की स्थिति में नहीं है।उसे पहले शांत कर सामान्य स्थिति में लाएं। दिल से मांगी गई माफी से स्थिति सामान्य हो जाएगी। यह हमारा बड़प्पन भी होगा कि जो व्यक्ति हमारे कारण दुखी हुआ है और हम अपनी गलती स्वीकार कर उसे सामान्य होने में मदद कर रहे हैं। फिर हुए नुकसान या असुविधा की पूर्ति के लिए तत्काल प्रयास करें। व्यर्थ की दलीलों में समय बर्बाद करने की बजाय तत्काल कदम उठाएं। इस तरह हम अपनी खामियों के बावजूद सम्मान भरोसा हासिल करेंगे। अन्यथा भावनाओं की गलत अभिव्यक्ति से आप हमेशा तनाव में रहेंगे, जो आपको समाधान से दूर और दूर ले जाएगा। साथियों बात अगर हम क्षमा देने की करें तो, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता,क्षमा करना तो शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण है।बाणभट्ट के हर्षचरित में उल्लेख किया गया है कि क्षमा सभी तपस्याओं का मूल है। महाभारत में कहा गया है कि क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण और समर्थ मनुष्यों का आभूषण है।' श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है- क्षमाशील को रोग नहीं सताता और न ही यमराज डराता है। साथियों बात अगर हम क्षमा में भावनात्मक मिश्रण से हानि की करें तो खासकर पारिवारिक झगड़ों में हम देखते हैं कि, पति का पत्नी से झगड़ा हो गया है। उनके बीच कोई समस्या हो सकती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि पत्नी का मूड खराब है तो वह बेटे पर गुस्सा उतारेगी। बेटे पर मां मामूली-सी बात पर चिढ़ाई तो वह अपने साथियों से लड़ पड़ा और हम जितनी कल्पना कर सकें उतना इस कहानी को विस्तार दे सकते हैं। भावनाएं यदि समस्या के स्रोत की दिशा में हो तो भी यह उसे सुलझाने की बजाय बड़ा बना देती हैं। यहीं पर बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई माफी मांगे इसकी बजाय भावनात्मक विस्फोट के कारण आखिर में स्थिति होगी कि हमें ही माफी मांगनी पड़ सकती है। साथियों बात अगर हम माफी मांगने में अफसोस और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी के तड़के की करें तो,मुझे अफसोस है, इन तीन छोटे शब्दों के बिना माफी वास्तव में माफी नहीं है। उनका उपयोग करने से हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम वास्तव में उस समस्या को उत्पन्न करने के लिए पछताते हैं जिसने शिकायत को प्रेरित किया। इन शब्दों के साथ माफी मांगने से हमको यह दिखाने में मदद मिलती है कि हम अतीत में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो, यह समझाते हुए कि जो हुआ अब आगे हमेशा एक अच्छा विचार होगा, भविष्य में गड़बड़ी से मुक्त रखने के लिए हम जो कुछ भी बदलने की योजना बना रहे हैं उसे रेखांकित करके उस सफलता पर निर्माण करना सबसे अच्छा है। साथिया बात अगर हम माफी मांगने की व्यवहारिकता की करें तो, यदि हम गलत हैं, आंशिक रूप से भी, किसी की मांग करने से पहले क्षमा मांगना बेहतर है। क्षमायाचना उन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है जिन्हें हल करना सामान्य शब्दों के लिए बहुत कठिन है। क्षमा की वांछनीयता इसमें शामिल लोगों की संस्कृति पर निर्भर करती है। शर्म की संस्कृति में , एक उच्च स्थिति वाले व्यक्ति से जबरन माफी मांगना एक बहुत ही मूल्यवान चीज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि माफी मांगने वाले व्यक्ति के सामाजिक अपमान को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाता है।शिष्टाचार दूसरों से अपेक्षा करने का मानक नहीं है, यह एक ऐसा मानक है जिसका आप स्वयं पालन करते हैं। यह कहना कभी आसान नहीं होता, मुझे क्षमा करें। लेकिन कभी-कभी, गलती के लिए माफी मांगना ही आपकी प्रतिष्ठा को रक्षा करने का एकमात्र तरीका है। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि क्षमा मांगना या देना भावनात्मक और मानसिक कल्याण का एक पहलू है जो सद्भाव और शांति स्थापित करने में मदद करता है वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई 2025, विभिन्न संस्कृतियों व पृष्ठभूमियों के लोगों में क्षमा, यह शांति व सुलह की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करता है,क्षमा दिवस मनाने से खुद को व दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जिससे एक अधिक दयालू और सहानुभूति पूर्ण दुनियाँ को बढ़ावा मिलता है।

विश्व में न्यायपालिकाओं का पावर-पीएम से लेकर एक आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है?

वैश्विक स्तरपर सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के प्रेस को मिलाकर चार स्तंभ होते हैं। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका व मीडिया, जो अपने-अपने स्तरपर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पावरफुल होते हैं, परंतु अक्सर हम देखते हैं कि न्यायपालिका के पावरक्षेत्र में पंचायत समिति सरपंच से लेकर पार्षद व विधायक से लेकर संसद तथा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री व राष्ट्र मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री व पूरी मीडिया के प्लेटफॉर्मस आते हैं,कोई अगर किसी भी कार्यक्षेत्र में कोई गड़बड़ी कानून का कोई तोड़ना उल्लंघन करना, भ्रष्टाचार करना या मानवाधिकार का हनन संविधान का उल्लंघन करता है तो इसे तो न्यायिक क्षेत्र के पावर में आ जाते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि साफ सुथरे ईमानदार व्यक्ति को डरने घबराने की जरूरत नहीं, परंतु भ्रष्टाचार गलत आचरण से तो न्यायिक दायरे में आना ही पड़ेगा। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलवार 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की पीएम को वहां के न्यायालय की संविधान पीठ ने7/2 के बहुमत से 1 जुलाई 2025 से पीएम पद के कार्य से निलंबित कर दिया है,जब तक संवैधानिक पीठ अपना फैसला नहीं सुनाती। पूरी दुनियाँ के प्रशासकीय व राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि विश्व के अनेक बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, इंदिरा गांधी सहित अनेकों नेताओं को इन न्यायिक शक्तियों का सामना करना पड़ा है जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे।न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में खास से आम तक सभी व्यक्तियों को एक समान संहिता लागू होकर सजा या बरी होना खूबसूरती है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्धजानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, विश्व में न्यायालय का पावर,पीएम से लेकर एक आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। साथियों बात अगर हम थाईलैंड की पीएम को संविधान पीठ द्वारा 7/2 बहुमत से पद से निलंबित करने की करें तो, संवैधानिक न्यायालय ने पीएम पाइतोंगटार्न शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है।उनपर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है।इस बातचीत के लीक होने के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से पीएम को पद से हटाया कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाई गईं तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है।पीएम ने खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वह पीएम के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे।किसी देश के पीएम को पद पर रहते हुए इस तरह से निलंबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। साथियों बात अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट की शक्तियों की प्रक्रिया का सामना करने की करें तो,अब तक अमेरिकी अदालतों ने ट्रम्प प्रशासन के कम से कम 180 कार्यकारी आदेशों और नीतियों पर स्थाई या अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। साथ ही, ट्रम्प ने 9 मुद्दों पर 11 प्रमुख फैसलों पर यू-टर्न लेते हुए पलटा है।रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने, संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी और विदेशी सहायता रोकने जैसे आदेशों को अवैध या असंवैधानिक ठहराया है।वहीं, ट्रम्प ने फेडरल फंडिंग फ्रीज, अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा और टैरिफ नीतियों जैसे फैसलों को कई बार बदला या वापस लिया है।ट्रम्प के वो आदेश जिन्हें कोर्ट ने बदला ट्रंप ने वॉयस ऑफ अमेरिका को खत्म करने का फैसला लिया था, जिसे कोलोराडो की अदालत ने अवैध ठहराया। पर्यावरण नियमों को कमजोर करने वाले आदेशों को भी कैलिफोर्निया की अदालत ने रोका। वजह- वे क्लीन एयर एक्ट का उल्लंघन करते थे वाशिंगटन की अदालत ने गैर अमेरिकियों के लिए, मतदान प्रतिबंध को असंवैधानिक माना। अप्रैल 2025 में एक हफ्ते में 11 मुकदमों में ट्रम्प प्रशासन को हार मिली।ट्रम्प के ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य अधिकारों को सीमित करने वाले आदेश को भी न्यूयॉर्क कोर्ट ने भेदभावपूर्ण ठहराते हुए अवैध ठहराया। इसके अलावा ट्रम्प के विदेशी फंडिंग से जुड़े आदेश को भी अदालत ने गलत माना।टैरिफ व कर्ज छूट के फैसले खुद पलटने को मजबूर हुए,ट्रम्प ने जिन नीतियों को बार-बार पलटा उनमें सबसे बड़ा मामला टैरिफ से जुड़ा है। साथ ही प्रवासी बच्चों की कर्ज छूट रोकने का फैसला भी आदेश के कुछ दिनों के भीतर ट्रम्प ने रद्द कर दिया।डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत इन्क्लोसा रोकथाम फंडिंग रद्द हुई, जिसे बाद में फिर बहाल किया गया।मेक्सिको-कनाडा के साथ व्यापार समझौते को रद्द करने की घोषणा की लेकिन दबाव के बाद इसे स्थगित किया। साथियों बात अगर हम भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का सामना करने की करें तो,राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सात मुख्य आरोप लगाए थे,जैसे - चुनाव में विमानों और हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरने के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेना, मतदाताओं में कपड़े और शराब बांटना,चुनाव में गाय और बछड़े जैसे धार्मिक प्रतीक का उपयोग, मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक मुफ्त में पहुंचाना और सीमा से अधिक खर्च करना, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने इन सात में पांच आरोपों को खारिज कर दिया,उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) के तहत इंदिरा गांधी को दो भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया, पहला - इंदिरा ने चुनाव में बेहतर संभावना प्राप्त करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में राज्य के गैजेटेड अधिकारियों जैसे डीएम, एसपी और इंजीनियरों की मदद ली, दूसरा, उन्होंने अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक गैजेटेड अधिकारी यशपाल कपूर की मदद ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में 12 जून, 1975 को अपने फैसले में इंदिरा के चुनाव को अवैध करार दिया था।

साथियों बात अगर हम इजराइल के पीएम नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का सामना करने की करें तो, आईसीसी के न्यायाधीशों ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था और बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी किए थे. साथियों बात अगर हमबांग्लादेश की पूर्व पीएम को 6 माह की कंटेंप्ट आफ कोर्ट की सजा की करें तो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दी गई, जिसमें कथित तौर पर शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और ट्रिब्यूनल को धमकी देते सुना गया था। तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति गोलाम मुर्तुजा मजुमदार ने यह फैसला सुनाया। साथियों बात अगर हम भारत में पीएम को हटाए जाने के प्रावधानों की करें तो,किसी देश के प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाए हुए उसे निलंबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे में यह हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या भारत में भी इस तरह से पीएम को निलंबित करना कोई कार्रवाई संभव है?भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए रहता है। पीएम के कार्यकाल के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसीलिए एक पदस्थ पीएम अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो,इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति केवल तबतक पीएम पद पर बना रह सकता है, जब तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसके विपक्ष में न हो,लेकिन अन्य परिस्थितियों में पीएम का कार्यकाल पांच साल से पहले भी खत्म हो सकता है,भारत में भी निलंबित किए जा सकते है पीएमभारत किसी भी कारणवश लोकसभा, प्रधानमंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करे और किसी कारणवश, प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य हो जाती है तो उस वक्त पीएमअपने पद का त्याग कर सकता है और राष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र सौंप सकता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री को निलंबित करने जैसा कोई नियम नहीं है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व में न्यायपालिकाओं का पावर-पीएम से लेकर एक आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? थाईलैंड की पीएम व डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू,इंदिरा गांधी सहित अनेकों अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को न्यायपालिका के फैसलों का सामना करना पड़ा है न्यायपालिकाओं की न्यायिक प्रक्रिया में खास से आम तक सभी व्यक्तियों को एक समान संहिता से लागू होकर सजा या बरी होना खूबसूरती है।

सम्पादकीय...

अमरीका को अपने ठेंगे पर रखा

भगवा भाइयों ने भी मोदी जी के विरोधियों को वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पूछो ही मत। एक-एक गिनकर, साल-महीनावार पूरी लिस्ट बनाकर बता दिया है कि मोदी जी को परदेस में कब-कब, कहां-कहां और कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं। और यह भी कि मोदी जी से पहले वाले प्रधानमंत्रियों को परदेस में कितने थोड़े अवार्ड मिले थे। कोई तुलना ही नहीं है भाई साहब। परदेसी अवार्डों में पहले वाले, मोदी का पासंग भी नहीं बैठेंगे। जिन नेहरू जी का इतना शोर सुनते थे कि दुनिया पता नहीं उन्हें कितना मानती थी, कि दुनिया उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पिताओं में गिनती थी, उन्हें दो, जी हां ठीक सुना फकत दो विदेशी अवार्ड मिले थे। और जिन इंदिरा गांधी ने कहते हैं कि दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया और अमरीका को अपने ठेंगे पर रखा, उन्हें भी ले-देकर सिर्फ दो विदेशी अवार्ड मिले थे। और राजीव गांधी को तो एक भी विदेशी अवार्ड नहीं मिला, बोफोर्स की तोप की बदनामी और श्रीलंका में हमले के सिवा। और अपने मोदी जी? सत्तर साल में भारत के सारे प्रधानमंत्रियों को मिलाकर भी जितने अवार्ड मिले होंगे, उससे कम से कम तीन गुना ज्यादा अवार्ड तो अब तक अपने मोदी जी की झोली में आ भी चुके हैं। जी हां ठीक सुना, पूरे चौबीस-पचीस अवार्ड। और अवार्ड मिलने का सिलसिला न सिर्फ लगातार जारी है, बल्कि तेज से तेज ही होता जा रहा है। पांच देशों की आठ दिन की यात्रा पर निकले मोदी जी, घाना और ट्रिनिडाड-टोबैगो से, दो अवार्ड तो अब तक बटोर भी चुके हैं, जबकि तीन देशों का दौरा अभी बाकी ही है। फिर मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल तो अभी शुरू ही हुआ है। ग्यारह साल में पचीस यानी साल में सिर्फ सवा दो विदेशी अवार्ड का औसत रहे तब भी, तीसरे कार्यकाल के अंत तक मोदी जी, तीन दर्जन तक तो आंकड़ा पहुंचा ही देंगे। उड़ती-उड़ती खबर तो यह भी सुनने को मिली है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बटोरने का विश्व रिकार्ड तो चालू विदेश यात्रा शुरू होने से बहुत पहले ही तोड़ चुके थे। सच पूछिए तो कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। अब तो बस मोदी जी अपना रिकार्ड इतना बड़ा करने में लगे हुए हैं कि उसे बाद में कोई, कभी भी न तोड़ पाए। अब इससे बढ़कर इसका सबूत क्या होगा कि दुनिया भारत को विश्व गुरु और मोदी जी को विश्व सम्राट मान चुकी है। पर हमें पता है कि जलकुकड़े विरोधी अब भी नहीं मानेंगे। उल्टे वे तो मोदी जी के इतने सारे अवार्ड बटोरने का ही मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि यह सम्मान पाना नहीं, यह तो अवार्ड वसूली है। मोदी जी छोटे-छोटे देशों को अपने दौरे के फायदे बताते हैं, फिर दौरे के लिए अवार्ड दिए जाने की शर्त लगाते हैं; इस तरह खोज-खोजकर ऐसे देशों से और ऐसे-ऐसे अवार्ड लाते हैं, जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं होते हैं। लेकिन, यह सब झूठ है। चौबीस-पचीस अवार्ड की इस गिनती में मोदी जी ने कोटलर अवार्ड को तो गिना तक नहीं है। सुनते हैं कि पहला और आखिरी कोटलर अवार्ड किसी चालू हिंदुस्तानी ने ही मोदी जी को पकड़ा दिया था। मोदी जी की भी बात सही है, विदेशी नहीं, तो अवार्ड नहीं। वर्ना कौन सा देसी अवार्ड है जो खुद ब खुद मोदी जी के चरणों में आकर नहीं गिर गया होता। मोदी जी चाहते तो हर रोज अवार्ड लेते बल्कि दिन में तीन-तीन बार। दिन में जितनी पोशाकें, उतने अवार्ड। जो गिनती अब तक दर्जनों में ही पहुंची है, हजारों में पहुंच जाती। इतने अवार्ड हो जाते, इतने अवार्ड हो जाते कि मोदी जी के नये बनने वाले महल में भी सजाकर रखने के लिए जगह कम पड़ जाती। बहुत से अवार्ड तो महल के कोनों में, ताखों पर, आलों में, शैया के नीचे पड़े रहते। राष्ट्रीय संग्रहालय की सभी वीथिओं में सिर्फ मोदी जी के अवार्ड रहते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा कुछ भी हो। परदेसी अवार्डों के साथ, देसी अवार्डों की मिलावट मोदी जी नहीं चाहते। देसी अवार्ड में चुनाव की जीत ही काफी है! चुनाव आयोग छठे-छमाहे तो मोदी जी को यह अवार्ड भी देता ही रहता है। अभी फरवरी में दिल्ली में दिया था। अब साल के आखिर में बिहार में देने की पूरी तैयारी है। इसके लिए करोड़ों वोटरों को चाहे 'हैं' से 'थे' करना पड़ जाए, चाहे मतदाता सूचियों में कितनी ही काट-छांट करनी पड़ जाए, पर जीत का अवार्ड मोदी जी को ही दिया जाएगा। आखिर, देश की इज्जत तो चुनाव आयोग के ही हाथ में है। मोदी जी को अगर जीत का अवार्ड भी नहीं दिया, तो दुनिया क्या कहेगी? जिसे खुद भारत वाले गद्दी का अवार्ड देने में हिचक रहे हों, उसे बाकी दुनिया विश्व गुरु का पद कैसे देगी! बेशक, मोदी जी के विरोधियों का परदेसी अवार्डों में छोटे-बड़े की बात करना, जान-बूझकर मोदी जी के नये भारत को बदनाम करना है। वर्ना यह तो मोदी जी की महानता है कि वह परदेस के मामले में एकदम समदर्शिता बरतते हैं। दूसरे देशों के बीच छोटा-बड़ा नहीं देखते हैं। और अपने सामने छोटा-बड़ा तो खैर बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। छोटे से छोटे देशों के, दूसरे-तीसरे नंबर के अवार्डों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, जितना कोई और बड़े देशों के नंबर एक के अवार्डों का करता होगा। जैसे भगवान प्रेम के भूखे बताए जाते हैं, मोदी जी बस विदेशी अवार्ड के भूखे हैं। छोटा-बड़ा नहीं देखते हैं, न देने वाले देश में और न मिलने वाले अवार्ड में। और क्यों देखें छोटा-बड़ा? आखिर, तमगा सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मोदी जी कुछ न कुछ तो भारत में ला ही रहे हैं। हम तो कहेंगे कि भारत के गौरव के विरोधी हैं जो मोदी जी के अवार्डों को देने वाले देश के आकार या अवार्ड के क्रमांक के हिसाब से नापने की कोशिश करते हैं। मोदी जी पक्के जनतंत्रवादी हैं, उनका नजरिया एकदम स्पष्ट है; जब चुनाव में सारा महत्व संख्या का होता है, तो क्या विश्व सम्राट के चुनाव में अवार्डों की संख्या का ही महत्व नहीं होगा? और बाकी कुछ चाहे हो या नहीं हो, विदेशी अवार्ड के मामले में तो मोदी जी ने गांधी-नेहरू परिवार को जोरदार तरीके से पीट ही दिया है, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक। साथ में वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी लपेटे में आ गए हैं। तो यह इतिहास की जरूरत है। मोदी जी का अगर कोई कसूर है तो सिर्फ इतना कि वह भर-भरकर विदेशी अवार्ड ला रहे हैं।

ठाकरे बंधुओं का 'मिलन'

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम उस वक्त देखने को मिला जब शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने लगभग 20 साल बाद मंच साझा किया। यह जश्न महाराष्ट्र सरकार द्वारा विवादास्पद त्रिभाषा नीति के सरकारी आदेश को वापस लेने के फैसले के बाद आयोजित किया गया। इस विजय रैली ने जहां एक तरफ मराठी अस्मिता और भाषा अधिकारों के मुद्दे को फिर से केन्द्र में ला दिया वहीं दूसरी ओर आगामी मुम्बई महानगर पालिका चुनावों और अन्य स्थानीय निकायों में संभावित गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। एक बड़ी हिन्दी भाषी आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिन्दी को लेकर विरोध को हवा मिलती रही है। वजह है मराठी पहचान पर जोर, स्थानीय राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते आए हैं। महाराष्ट्र में ये हिंदी विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि ये पचास के दशक से चला आ रहा है, जो सियासी वजहों से रह-रहकर उफान मारता रहा है। पचास के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट जिसमें आज का गुजरात और उत्तर-पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ। साठ के दशक में आंदोलन का असर दिखा। संसद ने मुम्बई पुनर्गठन कानून पास किया जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने। इसके छह साल बाद जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की तो उनका घोषित लक्ष्य था, बैंक की नौकरियों और कारोबार में दक्षिण भारतीयों और गुजराती लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी लोगों के मुद्दे उठाकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में गहरी पैठ बना ली। अस्सी के दशक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीयों और उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार रैली और आंदोलन किए। शिवसेना सत्ता में आई तो उसने दुकानों और संस्थानों में मराठी नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी। बैंकों और सरकारी दफ्तर में भी मराठी में काम शुरू करवाया। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को इसलिए पीटा क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पाया था। मुम्बई और महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों को पहले भी मारा-पीटा जाता रहा। ठाकरे बंधुओं के मिलन से पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति सुशील केडिया के कार्यालय में तोड़फोड़ की क्योंकि उन्होंने भी मराठी नहीं सीखने की बात कही थी। दक्षिण भारत में भी हिन्दी के विरोध में मोर्चाबंदी कर रखी है। ठाकरे बंधुओं का मेल-मिलाप विशुद्ध राजनीतिक कारणों से है, लेकिन दोनों ने मराठी गौरव को अपनाया और एक बार फिर हिन्दी के विरोध को हवा दी। यह कैसा तर्क है कि दोनों को हिन्दू हिन्दोस्तानी तो स्वीकार्य है, लेकिन हिन्दी नहीं। दरअसल भाषा का मुद्दा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करता है। महाराष्ट्र की सरकार ने विरोध को देखते हुए पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिन्दी को अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश बढ़ते राजनीतिक विरोध के चलते वापस ले लिया। देश में लगभग 65 करोड़ भारतीय हिन्दी जानते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। अहिन्दी भाषी राज्यों के राजनीतिज्ञ, कलाकार, लेखक हिन्दी सीखते हैं और बोलने का अभ्यास करते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिन्दी में डब कर रिलीज किया जाता है और नामी गिरामी दक्षिण भारतीय फिल्म स्टारों की राष्ट्रीय छवि हिन्दी के माध्यम से ही बनी है। मुम्बई फिल्म उद्योग भी हिन्दी सिनेमा के सहारे ही करोड़ों रुपए का व्यापार करता है। सवाल यह है कि फिर हिन्दी का इतना तीखा विरोध क्यों? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मेल-मिलाप से महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदल सकते हैं। खासकर मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे जैसे मराठी-बहुल शहरी क्षेत्रों में, जहां दोनों दलों का मजबूत जनाधार रहा है। वर्ली, सेवरी, लालबाग, परेल, वडाला, भायखला, भांडुप, विक्रोली और चेंबूर जैसे इलाकों में यह तालमेल काफी असर डाल सकता है, ये ऐसे इलाके हैं, जहां इन दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है।

पचास के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट जिसमें आज का गुजरात और उत्तर-पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ। साठ के दशक में आंदोलन का असर दिखा। संसद ने मुम्बई पुनर्गठन कानून पास किया जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने।

ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से उनका वोट बैंक मजबूत होगा, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों में जबरदस्त बढ़त मिल सकती है हालांकि ये गठबंधन आसान नहीं होगा। दोनों पार्टियों की विचारधाराएं, सांगठनिक संरचनाएं और अतीत की प्रतिद्वंद्विता अलग-अलग रही है। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के मुद्दों तक कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। दोनों नेताओं को एकसाथ आने के लिए आंतरिक असंतोष और प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना होगा। वर्ली की रैली, दरअसल इस बात का भी लिटमस टेस्ट था कि क्या ठाकरे बंधु मराठी जनमत को एकजुट कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ने अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है लेकिन हिन्दी विरोध के नाम पर हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब सबकी नजर ठाकरे बंधुओं की अगली रणनीति पर है। देखना होगा कि अब महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेते हैं?

उस नहीं, इस इमरजेंसी का भी विरोध है

मन कर रहा है इस बार इमरजेंसी पर कुछ लिखूं। आप कहेंगे, इमरजेंसी को गुजरे तो पचास साल बीत गए। अभी 25 जून को उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस समय लिखते तो मौजू रहता। पर मैं ना, लिखने के मामले में जरा दिग्भ्रांत हूं, दिक्कत होती है। अटक जाता हूं। ऐसा व्यक्ति जरा देर में बोलता है। बोलता देर में है पर उसका नोटिस लिया जाता है। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। नहीं, नहीं, मैं कोई अपनी और मगरमच्छ टाइप की कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूं। मैं तो स्कूल की बात बताना चाहता हूं। हां, मैं तब स्कूल जाता था। चौथी कक्षा के बाद की ही बात है। उस समय मैं शायद पांचवीं में पढ़ता था। या फिर छठी में। मेरी कक्षा में एक बच्चा था जो अटक अटक कर बोलता था। वह पहले अक्षर पर अटक जाता था और बाकी का पूरा शब्द सब के बाद बोलता था। जब सुबह सवेरे क्लास टीचर कक्षा में प्रवेश करती थीं तो सभी बच्चे समवेत स्वर में बोलते थे, गुडमार्निंग मैम। उसकी महीन आवाज सबसे बाद, सबसे अलग निकलती थी, मॉर्निंग मैम। मैडम, किसी और के बारे में पूछें या ना पूछें, पर अगर वह अलग आवाज नहीं आती थी तो जरूर पूछती थीं, उसका नाम ले कर पूछती थीं, नरेंदर नहीं आया आज! उसका नाम शायद यही था। हो सकता है कुछ और भी रहा हो। मैम, वह विदेश गया है। वह विदेश बहुत जाता था। उसके पापा बहुत अमीर थे। तो मैं आज इमरजेंसी पर लिख रहा हूं। जिन्होंने इमरजेंसी पर लिखना था, लिख लिया। पच्चीस जून से उनतीस जून तक लिख लिया। पर मैं आज लिख रहा हूं। लिख रहा हूं, ताकि सनद रहे। ताकि मेरा भी विरोध दर्ज हो। सिर्फ उस इमरजेंसी के खिलाफ ही नहीं, इस वाली, आज वाली इमरजेंसी के खिलाफ भी दर्ज हो। पचास साल पहले इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इमरजेंसी लगाई थी। 25 जून, 1975 को।1975 की घोषित इमरजेंसी। ये वो इमरजेंसी थी, जिसमें कम से कम इमरजेंसी का एलान तो हुआ था। एलान हुआ, प्रेस की गर्दन पकड़ी गई, नेताओं को जेल में डाला गया, नागरिक अधिकारों को बक्से में बंद किया गया और लोकतंत्र जैसे किसी और जमाने की वस्तु बन गई। फिर इंदिरा जी ने 19 महीने बाद कहा, ठीक है भई, बहुत हो गया। अब इमरजेंसी हटा देते हैं, चुनाव करा देते हैं। और जनता ने भी कहा, हां, बहुत हुआ, अब आप बैठ जाइए। यह सब एक कायदे-कानून के भीतर हुआ था। संविधान के अनुसार हुआ था। यह आधिकारिक इमरजेंसी थी और हमने अभी हाल में ही इस घटना की पचासवीं वर्षगांठ मनाई है। वर्षगांठ मनाई थी कि हमें याद रहे कि इतिहास में ऐसा कर्म भी हुआ था और हमें उसे दोबारा नहीं करना है। लेकिन वह इतिहास ही क्या जो अपने को दोहराये नहीं। इसीलिए तो कहावत है, इतिहास अपने को दोहराता है। जब इतिहास अपने को दोहराता ही है तो फिर हम वर्षगांठ मनाते ही क्यों हैं। क्या यह याद रखने के लिए कि यह गलती हुई थी, इसे दोहराना नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करण ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साथ पॅचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

बाबा लक्खी शाह वंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए घोषणा की, कि राज्य सरकार द्वारा जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ स्थित बाबा लक्खी शाह बावड़ी का सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। साथ ही गांव में उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 31 लाख रुपये और कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार व कुमारी आरती सिंह राव की तरफ से 11-11 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि समाज की सहमति से प्रदेश में किसी एक चौक और एक सड़क का नाम बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, उनके नाम से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण भी करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज यहां संत कबीर कुटीर पर बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करते हुए की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा लक्खी शाह वंजारा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज की ओर से उन्हें आज पगड़ी पहनाकर जो मान-सम्मान दिया गया है उसे वह कभी कम नहीं होने देंगे और सदैव इस सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे।

बाबा लखी शाह वंजारा ने गुरु भक्ति और साहस का अनूठा उदाहरण पेश किया

प्रदेशवासियों को बाबा लखी शाह वंजारा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इतिहास में एक अमर गाथा लिखी। उन्होंने कहा कि जब हम भारत की महान संस्कृति, विविधता और बलिदानी परंपरा की बात करते है, तो कई महान वीरों की छवि उभरती है, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। बाबा लक्खी शाह वंजारा उनमें से एक थे। वे ऐसे सिक्ख सेवक थे, जिन्होंने गुरु भक्ति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाता रहेगा।

वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लक्खी शाह वंजारा की कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। उन्होंने मुगलों का डटकर मुकाबला किया और धर्म की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया। भारत के इतिहास में सम्भवतः यह पहली घटना थी, जब किसी एक परिवार के 112 से अधिक सदस्यों द्वारा शहादत दी गई। उन्होंने कहा कि वंजारा समाज संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है, जिसने न केवल व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कर रही काम

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुष किसी भी धर्म व जाति के न होकर सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए सरकार 'संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना' के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इन योजनाओं से वंजारा समाज का भी उत्थान हो रहा है।

सरकार ने दशकों से बेघर घुमंतु जातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया

उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। घुमन्तु जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके परिवारों के पहचान पत्र बनाये गये हैं। अब इन्हें सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दशकों से बेघर रही घुमंतु जातियों को एक जगह बसाकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। सरकार द्वारा करनाल, पलवल व रोहतक शहरों के लिए आवेदन करने वाले घुमंतु जाति के गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए है।

इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत गरीबों को शहरों में प्लाट देने का काम शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर 15 हजार 256 गरीब परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज प्लाटों का कब्जा न पाने वाले 4 हजार 532 लोगों को अधिकार पत्र एवं 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना' के तहत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है। इस योजना के तहत 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 तक 2 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से भी मुक्ति दिलवाने के लिए पी.एम. सूर्य घर योजना चलाई है। अब तक 18 हजार से अधिक लोगों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं। इसके अलावा, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 17 लाख 51 हजार परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलैण्डर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में गरीब परिवारों का 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों का 2 हजार 745 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा, 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन' योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है।

बाबा लक्खी शाह वंजारा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा लक्खी शाह वंजारा ने हमें सिखाया कि सिर्फ तलवार से ही नहीं, बल्कि त्याग और साहस से समाज के कल्याण के लिए किये गये कार्यों से भी इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा' बनाने की ओर आगे बढ़ रहे है, हम सभी को बाबा लक्खी शाह वंजारा जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। इससे पूर्व विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वंजारा समाज के लोग मेहनती व साहसी है और इसी के बल पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिनका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री श्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, श्री जवाहर सैनी, बंजारा समाज के प्रधान जसमेर वंजारा, सुबेदार मेजर किशोरी लाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

- *मुख्यमंत्री ने बाबा लक्खी शाह वंजारा जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में की अनेक घोषणाएं
- *कुरुक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ स्थित बाबा लक्खी शाह बावड़ी का करवाया जाएगा सौंदर्यकरण
- *मुख्यमंत्री ने गांव ईशरगढ़ में बाबा लक्खी शाह की मूर्ति स्थापित करने व सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 31 लाख रुपये की राशि देने की करी घोषणा
- *प्रदेश में किसी एक चौक और एक सड़क का नाम बाबा लक्खी शाह वंजारा के नाम पर रखा जाएगा- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

एक नजर

स्वास्थ्य मंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

चंडीगढ़ । हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। आरती सिंह राव ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाओं की आपूर्ति और व्यक्तिगत चिकित्सा सहायता से संबंधित थीं। मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनहित के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतेगा। आरती सिंह राव ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनना और उनका त्वरित समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनकल्याणकारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई के बाद मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की तथा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

स्वच्छता सरकार व समाज की साझा जिम्मेदारी : विपुल गोयल

*विकास की नई उड़ान भर रहा है फरीदाबाद : राजेश नगर

*सफाई अपनाओ – बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि स्वच्छता को लेकर देश में चल रहे प्रयासों ने आज एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। एक समय था जब स्वच्छता पर सार्वजनिक मंचों से चर्चा नहीं होती थी, लेकिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान कर पूरे देश को एक नई दिशा दी। सफाई अपनाओ - बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत नागरिकों को जागरूक करने के लिए आज फरीदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और महापौर प्रवीण जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की शपथ के साथ की गई। श्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए सफाई अपनाओ - बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत देश और प्रदेश भर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह अभियान प्रदेश के कोने-कोने में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट मत है कि जब तक हर व्यक्ति अपने घर, गली, मोहल्ले और आसपास की सफाई को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत- का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो उसी भावना से अपने आस-पड़ोस को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तभी हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ और सशक्त बन पाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने नागरिकों से स्वच्छता के प्रति सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने आमजन से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम 100 घंटे और प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का श्रमदान स्वेच्छा से करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने घर व कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में स्वच्छता का संकल्प ले ले तो पूरे शहर की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता, सहभागिता और स्वेच्छा से किया गया श्रमदान ही असली राष्ट्र सेवा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि फरीदाबाद शहर आज लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है और राज्य के प्रमुख औद्योगिक व शहरी केंद्र के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और परिवहन जैसे क्षेत्रों में किए गए निवेश और योजनाओं के कारण फरीदाबाद का कायाकल्प होता दिख रहा है। विशेष रूप से मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से फरीदाबाद को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली-मुंबई के बीच तेज़ यात्रा का मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि फरीदाबाद को राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में और भी बेहतर ढंग से जोड़ेगा, जिससे व्यापार, उद्योग और आवागमन में अत्यधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की उस दूरदर्शिता को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वच्छता ही सेवा है। हरियाणा सरकार द्वारा इस भावना को न केवल अपनाया गया है, बल्कि उसे योजनाबद्ध ढंग से लागू भी किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो रहा है। अब यह जिम्मेदारी हम सभी की है कि इस जन आंदोलन में सहभागिता निभाते हुए स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, स्वच्छ और विकसित भारत की नींव मजबूत करें। मेयर प्रवीण जोशी ने इस दौरान लोगों को यह संदेश दिया गया कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं कि उसमें गंदगी न आए, उसी प्रकार हमें अपने शहर को भी स्वच्छ रखना है। इस बात पर बल दिया गया कि सफाई केवल सरकारी तंत्र की नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक यह संकल्प ले कि जैसे अपने घर को साफ रखते है वैसे ही सार्वजनिक स्थलों की सफाई में भी योगदान देंगे, तो -स्वच्छ भारत- का सपना जल्दी साकार हो सकता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल, गोयल, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और महापौर प्रवीण जोशी ने सफाई कर्मियों को पीपीई किट वितरित की और साथ ही स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नरवाना के विकास के प्रति वचनबद्ध होकर किया जा रहा है निरंतर कार्य : कैबिनेट मंत्री

चंडीगढ़ । हरियाणा के सामाजिक न्याय,अधिकारिता अनुसूचित जातीय एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि नरवाना के विकास के प्रति वचनबद्ध होकर निरन्तर कार्य किया जा रहा है। नरवाना के सभी वार्डों के विकासात्मक कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर हुई है। भविष्य में भी प्रत्येक पार्षद अपने- अपने वार्ड में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों की सूची दें ताकि बजट मुहैया करवाकर विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में नगर परिषद की हाउस बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में 20-20 बैंच उपलब्ध करवाए जाएंगे और ये कार्य पार्षदों की निगरानी में करवाया जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की आय के स्त्रोत बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएं ताकि विकासात्मक कार्य निरन्तर चलते रहें। नगर परिषद के लिए करीब 17 करोड़ रुपये की राशि का बजट मंजूर करवाया गया है जिसमें से एक किस्त आ चुकी है। जिससे सभी वार्डों के विकास कार्यों की सूची बना दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी पार्षद अपने वार्डों में आपसी तालमेल से कार्य करें अगर किसी पार्षद को कोई समस्या आ रही है तो वे तुरंत उनके संज्ञान में लाएं। शहर के सर्वांगीण विकास हेतु पार्षदों को दायित्व सौंपकर अलग-अलग कमेटियां गठित की गई है जो विकासात्मक कार्यों व आमजन को दी जाने वाली अन्य मूलभूत सुविधाओं पर निगरानी रखेंगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वित्त कार्य, पब्लिक वर्क, भवन, स्वच्छता, जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, पैट, स्ट्रीट लाईट मैंटिनेंस, विज्ञापन आदि कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग कमेटियां हाउस की सहमति से गठित की गई है। इनका कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी : डॉ. प्रफुल्ल रंजन

चंडीगढ़ ।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रेवस बैंक लिमिटेड (हस्को बैंक) द्वारा पंचकूला में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। हस्को बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन ने स्वयं पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, शुद्ध पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यह न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है। पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण को एक तरह से रीढ़ है। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाते हुए पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को

हस्को बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन सहित कर्मचारियों ने चलाया पौधारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

निभाएं। अभियान के अंतर्गत 200 छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। ये पौधे सेक्टर-20 पंचकूला स्थित हस्को बैंक सोसायटी परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों में लगाए गए, ताकि इनकी नियमित देखरेख संभव हो सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे तथा उनके द्वारा रोपित किए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर हस्को बैंक के महा प्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा, प्रबंधक श्री यशवीर, सहायक प्रबंधक श्री रजत कश्यप, श्री तर्ष भारती, श्री सूरज सिंह, श्री अतुल व अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

सामूहिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा : कृष्ण कुमार बेदी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के सामाजिक न्याय,अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव हंसडैहर में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से जुड़े कार्यों और हर वर्ग के कल्याण एवं उत्थान की दिशा में क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सामूहिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति बेहिचक अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकता है। मंत्री ने कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, उस पर वो खरा उतरेंगे। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव हंसडैहर में धन्यवादी दौरा कार्यक्रम के तहत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से तैयार ई लाइब्रेरी का

-कैबिनेट मंत्री ने गांव हंसडैहर में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, 37 लाख रुपये की परियोजनाओं की दी सौगात

उद्घाटन किया तथा 11 लाख रुपये की धनराशि से बनने वाले बिन्दुसर तीर्थ के लंगर हॉल और 11 लाख रुपये से बनने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले रोड के निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई मांगों को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हर वर्ग के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने इस बीच घोषणा करते हुए कहा कि गांव में सीवर को गंदे नाले से जोड़ा जाएगा। एक मिनी स्टेडियम और ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। स्कूल में सोलर प्लेट भी लगवाई जाएंगी। रेवर तक जमीन देने की शर्त पर 4 किलोमीटर की सड़क को पक्का कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। चुनाव के दौरान जो जनसमर्थन गांव की जनता ने उन्हें दिया, उसके लिए वे हमेशा ऋणी रहेंगे और उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को आपसी तालमेल के साथ सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए ताकि गांव के विकास को गति मिले। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी का ग्रामीण युवाओं द्वारा फूल मालाओं, पगड़ी, शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक पिरथी नंबरदार, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि विशाल मिर्धा सरपंच जरनैल सहित काफी संख्या में गणमान्य मौजूद थे।

घरौंडा हलके में विधानसभा अध्यक्ष ने दी सौगात, 2 करोड़ 12 लाख के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

चंडीगढ़ ।

घरौंडा हलके में निरंतर विकासकार्यों की झड़ी लगी हुई है। हलके को नित नई-नई परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सोमवार को 2 करोड़ 12 लाख रुपये की चार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गांव डबरकों पार (जम्मुखाला) और सुभरी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां विकास परियोजनाओं कि शिलान्यास किया गया। गांव सुभरी और डबरकी पार (जम्मुखाला) के लोगों ने मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया। उन्होंने डबरकी पार (जम्मुखाला) में नगर खेड़ा से यमुना बांध तक रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पौने सौ फुट लंबे इस रास्ते के निर्माण पर 1 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च होंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से बनवाए जाने वाले इस रास्ते का निर्माण कार्य एक साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने जम्मुखाला/डबरकी गांव में 65 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। इसमें हॉल, शौचालय, चार दीवारी आदि का निर्माण कराया जाएगा। कार्य एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सुभरी गांव में 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की चारदीवारी और एसएचजी की महिलाओं के लिए हॉल का भी शिलान्यास किया। इन पर क्रमशः बीस और आठ लाख रुपये की लागत आएगी। दोनों का निर्माण कार्य तीन महीने में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि हलके के हर गांव में महिलाओं के लिए अलग चौपाल/भवन बने। कई गांवों में ये बनाए जा चुके है। दिसंबर 2026 तक हर गांव में महिला चौपाल बनवा दी जाएंगी। इससे

डबरकी पार (जम्मुखाला) और सुभरी गांव में चार विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास शुगर मिल में सुनीं आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश

महिलाओं को बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की सुविधा हासिल हो सकेगी। सरकार मातृ शक्ति की आमदन बढ़ाने के प्रति गंभीर है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के लिए घरौंडा में 3 करोड़ से बनने वाले ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इसके लिए 1 एकड़ जमीन पंचायत से ली गई थी। यह प्रशिक्षण संस्थान डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां एसएचजी की महिलाएं अपने उत्पादों के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। बाजार की मांग अनुसार तैयार किए जाने वाले उत्पादों से उनकी आय में इजाफा होगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि हलके में रिंग रोड और मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी आरंभ होने से न केवल यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रिंग रोड बनने से क्षेत्र में बड़ी कंपनियां आएंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि सुभरी गांव में एससी वर्ग के लिए चौपाल मंजूर हो चुकी है। इस पर 15 लाख रुपये की लागत आएगी। पिछली प्लान के अधूरे कार्यों का तेजी से पूरा कराया जा रहा है। उस समय कोरोना के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि हलके के लोगों के लिए उनके द्वार 24 घंटे खुले हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने करनाल के शुगर मिल के अतिथि गृह में कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निष्पादन के निर्देश दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों से रूबरू होकर कई तरह की नई समस्याओं का पता चलता है और उनके निवारण के लिए यथासंभव कदम उठाए जाते हैं। कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। कुछ मांगों को योजना में जोड़कर आगे बढ़ाया जाता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा-पंजाब में पानी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई है। हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। एक अन्य सवाल पर कहा कि जिला में संभावित बाढ़ से बचाव के लिए यमुना के तटबंधों को मजबूत किया गया है। उन्होंने खुद गत दिनों यमुना बांध का दौरा कर कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया था।

चुनाव आयोग पूरी तरह से कन्फ्यूज

बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश, तेजस्वी यादव का आरोप, भ्रमित है चुनाव आयोग

■ चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने खोला मोर्चा, तेजस्वी ने पूछे कई सवाल; चक्काजाम का भी एलान

पटना।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर) पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके समक्ष अपने सवाल रखे थे. चिंता की बात यह है कि हमें अभी तक चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली है. आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर के रूप में काम करता है और उसके पास जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है. कल चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग निर्देश जारी किए, इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग भ्रमित है. तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नई श्रम संहिता और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित "चक्का जाम में शामिल होने के लिए बुधवार को पटना पहुंचेंगे. इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (इंडिया) के नेताओं ने यह जानकारी दी. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और वाम दलों के नेताओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई. कुमार ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. यहां चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च प्रस्तावित है. तेजस्वी यादव ने कहा, "हम पटना में राहुल गांधी के साथ रहेंगे, लेकिन आंदोलन पूरे बिहार में किया जाएगा. हम श्रम संहिता के खिलाफ चक्का जाम को समर्थन दे रहे हैं जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समान ही लोकतंत्र पर हमला है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. यादव ने आरोप लगाया कि इस कवायद के माध्यम से भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

उच्चतम न्यायालय में 10 जुलाई को है सुनवाई

उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग के बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है.

उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों के मर्जर को हाईकोर्ट की हरी झंडी

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका को खारिज करते हुए मर्जर को हरी झंडी दे दी है. सीतापुर के 51 बच्चों ने सरकार की स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ याचिका दी थी. सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है. बता दें यूपी के 50,00 स्कूलों का मर्जर होना है. न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने फैसला सुनाया. सरकार द्वारा इस आदेश को 16 जून 2025 को जारी किया गया था. इसके तहत कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना है. सीतापुर के अलावा पीलीभीत के ब्लॉक बिलसंडा के ग्राम चांदपुर निवासी सुभाष, यशपाल यादव और अरविंद कुमार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय को चुनौती दी है. सोमवार को ही लोगों ने सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति के खिलाफ याचिका दायर की गई है. याचिका में राज्य सरकार, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज, क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, बिलसंडा को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय करने की बात कही है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश न केवल बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को भी प्रभावित करता है. इस याचिका पर दो से तीन दिन में सुनवाई हो सकती है.

मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी? राहुल गांधी फिर साधा केंद्र पर निशाना

नई दिल्ली।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर जेन स्ट्रीट पर सेबी की विस्फोटक कार्रवाई को लेकर तीखा हमला किया, जिसने भारत के 6.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजी बाजार के बुनियादी ढांचे में भूचाल ला दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने 2024 में साफ कहा था - F&O बाजार बड़े खिलाड़ियों का खेल बन चुका है, और छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है। अब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ की चालाकी की।

सेबी इतने समय तक चुप क्यों रही? राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी? और कितने बड़े शार्क अब भी रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट कर रहे हैं? हर मामले में साफ दिख रहा है - मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है, और आम निवेशकों को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है। जेन स्ट्रीट अमेरिका में स्थित एक प्रसिद्ध स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म है, जो 45 से अधिक देशों में सक्रिय है। सेबी ने हाल ही में इस फर्म पर भारत में स्टॉक और इंडेक्स की कीमतों में हेरफेर करके अपने ऑप्शन ट्रेड को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। सेबी के अनुसार, जेन स्ट्रीट ने पहले कीमतों को बढ़ाने के लिए स्टॉक खरीदकर और फिर बाद में ऑप्शन सेगमेंट में गिरती कीमतों से पैसे बनाने के लिए उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमाया। नियामक ने इन ट्रेडों से जुड़े 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के मुनाफे को फ्रीज कर दिया है और जेन स्ट्रीट और इसकी भारतीय शाखा को बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने चल रही जांच के तहत उनके बैंक और डीमैट खातों को भी फ्रीज कर दिया है।

जेन स्ट्रीट ग्रुप (जेएस ग्रुप) से जुड़ी चार संस्थाओं- जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, जेएसआई2 इन्वेस्टमेंट्स, जेन स्ट्रीट सिंगापुर और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग- को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों में सौदे करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बिहार विधानसभा चुनावों में राजद को पूर्ण समर्थन देगी सपा : अखिलेश यादव

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को पूरा समर्थन देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में हम लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने नीतीश कुमार और पर तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। हम तो नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का कोई इरादा नहीं है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार जी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम एक बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब देखिए- वह मुख्यमंत्री पद से ही 'रिटायर' हो जाएंगे। भाजपा उन्हें 'रिटायर' होने के लिए मजबूर करेगी।

हमलोग तो पीएम बनाना चाहते थे, सीएम ही रह गए नीतीश - अखिलेश

सत्तारूढ़ भाजपा और उसके वैचारिक रुख पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि मैं केवल एक ही बात जानता हूं- सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है, वही सच्चा सनातन मार्ग है। जो लोग अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं और बच्चों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे खुद को सनातनी नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में सिर्फ 'भगवा वस्त्र' पहनने से कोई 'बाबा' या योगी नहीं बन जाता। असली पहचान विचार और आचरण से होती है।

26/11 मुंबई हमले के साज़िशकर्ता तहव्वुर ने उगले कई राज, पाक को किया बेनकाब

नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के अहम साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी गई अपनी पहली पूछताछ में पाकिस्तान की गहरी भूमिका का खुलासा किया है. अमेरिका से अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित किए गए राणा ने बताया कि वह पाकिस्तान सेना का भरोसेमंद व्यक्ति था और उसे खाड़ी युद्ध के दौरान गुप्त मिशन पर सऊदी अरब भी भेजा गया था. राणा ने बताया कि उसने 1986 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और इसके बाद क्वेटा में बतौर कैप्टन डॉक्टर सेना में कमीशन प्राप्त किया. वह सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन-बालोत्रा जैसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में तैनात रहा. राणा के मुताबिक, उसका सह-साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली 2003 से 2004 के बीच लश्कर-ए-तैयबा के तीन प्रशिक्षण शिविरों में शामिल हुआ था. हेडली ने खुद राणा को बताया था कि लश्कर विचारधारा से अधिक जासूसी नेटवर्क के रूप में काम करता है.

भयानक हादसे में 3 महिलाओं की मौत, बच्चों सहित 15 लोग घायल

शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में सोमवार को एक मल्टी-यूटिलिटी वाहन (एमयूवी) के पेड़ से टकरा जाने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और बच्चों सहित 15 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब पांच बजे जोरा गांव के पास हुई। छत्तीसगढ़ के पंजीकरण नंबर वाली एसयूवी में 20 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ब्योहारी पुलिस थाने के प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि वाहन सवार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से छत्तीसगढ़ लौट रहे थे, तभी वाहन पेड़ से टकरा गया। उन्होंने बताया कि गायत्री कवर, मालती पटेल और इंदिरा बाई नाम की तीन महिलाओं की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए।

पौधरोपण महाभियान-2025: सीएम योगी अयोध्या और आजमगढ़ में करेंगे पौधरोपण, बनेगा नया रिकार्ड

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में बुधवार को पौधरोपण महाभियान-2025 के तहत एक दिन में 37 करोड़ पौधरोपण का रिकार्ड बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या और आजमगढ़ में पौधरोपण करेंगे। उनके साथ वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण सक्सेना, वन राज्यमंत्री केपी मलिक भी रहेंगे। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बाराबंकी में पौधरोपण करेंगी। यहां प्रदेश सरकार की तरफ से राज्यमंत्री सतीश शर्मा रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ तथा ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण कर अभियान को सफल बनाएंगे। योगी सरकार के मंत्री सभी 75 जिलों में रहेंगे। कैबिनेट, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व राज्यमंत्रियों को पौधरोपण करने वाले जनपदों में बुधवार को पौधरोपण करना होगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, सूर्यप्रताप शाही अयोध्या, स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर, बेबीरानी मौर्य अलीगढ़, चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा, जयवीर सिंह मैनपुरी, धर्मपाल सिंह बरेली, नंदगोपाल गुप्ता 'नंदी'प्रयागराज, अनिल राजभर आजमगढ़, राकेश सचान कानपुर देहात, एके शर्मा जौनपुर, योगेंद्र उपाध्याय आगरा, आशीष पटेल मीरजापुर, डॉ. संजय निषाद अंबेडकरनगर, ओमप्रकाश राजभर गाजीपुर, दारा सिंह चौहान देवरिया, सुनील कुमार शर्मा गाजियाबाद और अनिल कुमार बिजनौर में पौधरोपण करेंगे। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल कानपुर नगर, कपिलदेव अग्रवाल मुजफ्फरनगर, रविंद्र जायसवाल वाराणसी, संदीप सिंह एटा, गुलाब देवी संभल, गिरीश यादव प्रतापगढ़, धर्मवीर प्रजापति झांसी, असीम अरुण कन्नौज, जेपीएस राठौर मुरादाबाद, दयाशंकर सिंह बलिया, नरेंद्र कश्यप हापुड़, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली, दयाशंकर मिश्र दयालु चंदौली में पौधरोपण महाभियान का हिस्सा बनेंगे।

बहुत बड़े बॉस हो तो आओ बिहार, पटक-पटककर मारेंगे- राज ठाकरे को निशिकांत दुबे की चुनौती

गुवाहाटी। मुंबई में मराठी न बोलने पर हिंदीभाषियों के साथ मारपीट का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है. तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को घेर रही है.

अब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती दे डाली. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है, तो वह बिहार आकर दिखाएं, पटक-पटककर मारा जाएगा. गुवाहाटी में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे राज ठाकरे पर खूब बरसे.

हमारे पैसे पर पल रहे हो...

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आप किसकी रोटी खा रहे हो? टाटा, बिरला, रिलायंस की महाराष्ट्र में यूनिट तक नहीं है. टाटा ने पहली फैक्ट्री तब के बिहार में बनाई. हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो. कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास, सारे माइंस हमारे पास है या फिर झारखंड के पास है और छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, ओडिशा के पास है पर आपके पास कौन सी माइंस है. हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है. कौन कुत्ता और कौन शेर, खुद ही फैसला कर लो. बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि रिफाइनरी अगर रिलायंस ने लगाई है, तो गुजरात में लगाई है. सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भी गुजरात में आ रही है, आप लाडसाहेबी कर रहे हो. आपमें हिम्मत है तो उर्दूभाषी को भी मारो, तेलुगु-तमिलभाषी को भी मारो. अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो. अगर इतने बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पटक-पटक कर मारेंगे. हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है. हम छत्रपति शाहूजी और शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं.

हम सभी का सम्मान करते है...

तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं. उन सबों ने चाहे तिलक हों या फिर चाहे लाजपत राय हों, आजादी के आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले हों इन सभी ने बड़ा योगदान दिया है. हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं. भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज जो वोट बैंक की राजनीति, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और यह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहे हैं, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं.

भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, डायरेक्टर को भेजे ई-मेल की जांच में जुटी टीम

भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकीभरा ईमेल मिलते ही सनसनी फैल गई। ये ईमेल रविवार को एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया। इसमें बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं और किसी भी वक्त विस्फोट कर एयरपोर्ट को उड़ा दिया जा सकता है। बता दें कि बीते कुछ महीनों से लगातार भोपाल में अलग-अलग जगह बम उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये चौथी धमकी है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने भोपाल के गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमानन सुरक्षा नियमों के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने ऐहतियातन जांच की। हालांकि एयरपोर्ट पर संचालन नहीं रोका गया। पुलिस और साइबर सेल की टीमें अब इस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं।

इस बार की जनगणना होगी खास, नागरिक खुद कर सकेंगे गणना; लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 2027 में जनगणना की घोषणा की है। यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। इसको लेकर ताजा अपडेट आया है। अधिकारियों ने सोमवार (07 जुलाई, 2025) को कहा कि आगामी जनगणना के दौरान नागरिक खुद गणना कर सकेंगे और इसके लिए खास वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि देश की पहली डिजिटल जनगणना में गणना करने वाले एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नागरिकों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे। ऐसा देश में पहली बार होगा कि नागरिकों को वेब पोर्टल के जरिए खुद गणना करने का मौका मिलेगा। ये पोर्टल दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। एक अधिकारी ने कहा डिजिटल जनगणना पहल जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। डेटा इकट्ठा करने और इसे सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने के लिए पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जनगणना डेटा जल्दी उपलब्ध होगा।

हिमाचल प्रदेश में बारिश ने उग्र रूप में मचाया तांडव! आपदा में अबतक 78 लोगों की मौत

शिमला। हिमाचल में मानसून का तांडव उग्र रूप में देखने को मिला है। राज्य का मंडी शहर इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की व्यापक तबाही में अब तक 78 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल है। इसके अलावा अभी भी 31 लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल में मानसून का तांडव उग्र रूप में देखने को मिला है। राज्य का मंडी शहर इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की व्यापक तबाही में अब तक 78 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल है। इसके अलावा अभी भी 31 लोगों के लापता होने की खबर है। 20 जून से अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य को तबाह कर दिया है, जिससे घरों, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि धुनाग में एक विश्वसनीय स्थानीय बैंक को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है, क्योंकि चार जिलों में संभावित भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।

बिजली-पानी को तरस रही दिल्ली, नेता बना रहे फूलकुमारी निवास और शौचमहल, कांग्रेस का बड़ा हमला

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी नेताओं पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि, जब दिल्लीवासी जल और बिजली संकट से परेशान हैं, तब बीजेपी नेता जनता के टैक्स से ऐशो-आराम की जिंदगी बिता रहे हैं. उन्होंने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के सरकारी आवास को 'शौचमहल' की संज्ञा देते हुए कहा कि यह वही ढकोसला है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'फूलकुमारी निवास' में देखा गया था. यादव ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि श्यामनाथ मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 पर 2.35 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हो चुका है, जिसमें अकेले 94.69 लाख रुपये शौचालय और स्नानगृह के नवीनीकरण पर खर्च हुए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि महंगी टाइल्स, लग्जरी शॉवर और विदेशी फिटिंग्स के जरिए जनता के पैसों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है. जहां एक ओर दिल्ली की जनता बिजली कटौती और जल संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष के घर पर 94.93 लाख रुपये सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार्यों पर और 44.82 लाख रुपये अन्य मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जा रहे हैं. यादव ने कहा कि यह खर्च 'फूलकुमारी निवास' से भी अधिक है. यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में अब होड़ चल रही है कि कौन अपने बंगले पर जनता का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, जो आने वाले समय में शीशमहल' की तरह धीरे-धीरे कई गुना बढ़ सकता है. बीजेपी नेता एक-दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद में हैं, जबकि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने बीजेपी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि मंत्री प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता के बीच चल रही रस्साकशी के चलते अब कैबिनेट के बिना ही योजनाएं पास की जा रही हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएमओ की निगरानी वाली समिति को कमान सौंपना और अब कैबिनेट से छूट देना, बीजेपी के आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है. प्रदेश अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 1993 से 1998 के बीच बीजेपी ने सत्ता संघर्ष में तीन मुख्यमंत्री बदले थे.

आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है. उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भी बीजेपी सत्ता की लालसा और वैमनस्य की होड़ से मुक्त नहीं हो पाई है, और यह दिल्ली की जनता के लिए चिंता का विषय है. देवेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि यही रवैया जारी रहा, तो दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट सिर्फ नेताओं की सुख-सुविधाओं पर खर्च हो जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को सत्ता में आए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन घोषणापत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. अंत में उन्होंने कहा कि, जनता सब देख रही है. जैसे जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी केजरीवाल सरकार को सबक सिखाया, वैसे ही समय आने पर बीजेपी को भी जवाब मिलेगा.